साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 17-23 मार्च 2025 वर्ष-10, अंक-48

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

मोहन के बजट से अन्नदाता खुश

मोहन के बजट ने सबका मन मोह लिया है।इस बजट से होली की खुशियां दोगुनी और इंद्रधनुषी रंग की तरह सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' पंक्तियां चरितार्थ हुई हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा दोनों प्रदेश के विकास के लिए एक सिक्के के दो पहलू की तरह विकास का पहिया घुमाने में लगे हुए हैं। भोपाल इन्वेस्टर्स समिट की प्लानिंग बजट से पहले करके मोहन सरकार ने उद्योग जगत की सलाह और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए 39 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने के साथ-साथ प्रदेश की अधोसंरचना - विनिर्माण पर सबसे अधिक बजट में प्रावधान करके विपक्ष को भी निरुत्तर कर दिया है। इस बार मोहन सरकार ने गीता भवन निर्माण, श्रीकृष्ण पाथेय और राम वन गमन पथ के लिए अलग से बजट में प्रावधान करके होली के त्योहार की खुशियों को डबल करने का काम किया है। जिससे धर्म प्रेमियों में उल्लास का वातावरण बन गया है। मोहन सरकार ने मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहु एक की पंक्तियों के अनुसार प्रदेश के सभी वर्गों- मजदूर-बेरोजगार-किसान-उद्यमी- महिला और कर्मचारी सभी का ध्यान रखते हुए वित्तीय जटिलता के बावजूद सभी को खुश रखने का प्रयास किया है। होली का त्योहार प्रेम सौहाद्र और अपनत्व का है। होली त्योहार की खासियत है कि यहां सभी एक जैसे गुलाल के रंग में रंगे होते हैं न कोई निर्धन न कोई अमीर... उच्च और निम्न की परिभाषा से दूर समानता का त्योहार होली है। बजट में विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति पर खास फोकस किया गया है। प्रदेश में जनभागीदारी के माध्यम से संस्थाओं के निर्माण के लिए निजी निवेश संपत्ति का निर्माण प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि निजी निवेश से शासकीय सम्पत्ति एवं संस्थाओं के संचालन के लिए योजना बना रही है। इससे निजी क्षेत्र में अपनाए जा रहे बेहतर प्रबंधन माडलों को शासकीय संस्थाओं में भी लागू किया जा सके। इस योजना के विचार क्षेत्र में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं और छात्रावासों का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आधारित संचालन किया जाना प्रस्तावित है। एक नवाचारी उपकरण के रूप में सोशल इम्पेक्ट बांड जारी किए जाएंगे। इसमें सेवा प्रदाता, हितग्राहियों को सेवा प्रदान करने के लिए रिस्क फंडर्स से धन जुटाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सोशल स्टॉक एक्सचेंज उक्त सम्पूर्ण कार्य को संपादित करने के लिए एक कॉमन प्लेटफार्म के रूप में काम करता है।

बजट 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ का: एदल सिंह कंषाना को मिला 11100.12 करोड़

कृषि-पंचायत विभाग पर खूब धनवर्षा

बजट आवंटन के हिसाब से टॉप-3

-जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम (विभाग-3)-वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यकी 93932 करोड़

-डॉ. मोहन यादव, सीएम जीएसडी, गृह, जेल, औद्योगिक नीति, जनसम्पर्क, खनिज समेत 14 विभाग-40491.51 करोड़

-उदय प्रताप सिंह, मंत्री (विभाग-2)-परिवहन, स्कूल शिक्षा-36723.99 करोड़

भोपाल। जागत गांव हमार

मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट विधानसभा में उप मुख्यमंत्री-वित्त जगदीश देवड़ा ने पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। यह बजट 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का है। बजट में सबसे राहत की बात यह है कि सरकार ने जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। वहीं मंत्रियों के विभागों के बजट पर नजर डाली जाए तो लगभग सबको भरपूर राशि आवंटित की गई है। बजट आवंटन में सीएम डॉ. मोहन यादव अपने 14 विभागों के साथ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बाद सबसे आगे हैं। सीएम के पास मौजूद विभागों को 40 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट मिला है। वहीं देवड़ा के पास वित्त, वाणिज्य और योजना विभाग को मिलाकर करीब 94 हजार करोड़ का बजट मिला है। तीसरे नंबर पर 36 हजार करोड़ से अधिक बजट स्कूल शिक्षा व परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के पास है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल के पास तीन विभाग हैं। उनके विभागों को 33 हजार करोड़ से अधिक का बजट मिला है। वहीं एदल सिंह कंषाना के कृषि विभाग को 11100.12 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- वित्त मंत्री देवड़ा के तीन विभागों को सबसे ज्यादा 94 हजार करोड़
- बजट में मोहन नंबर-2: कुल 14 विभाग, 40 हजार करोड़ मिले
- मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप बजट में तीसरे पर
- सचिवालय के अंतर्गत 286 करोड़ रुपए का प्रावधान
- मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान के अंतर्गत 200 करोड़
- राज्य लोकसेवा आयोग के अंतर्गत 116 करोड़ रुपए
- लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के अंतर्गत 78 करोड़
- राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत 72 करोड़
- लोक आयुक्त के अंतर्गत 70 करोड़ का प्रावधान

चार कद्दावर मंत्रियों का बजट 11 हजार करोड़ रुपए बढ़ा

राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम

2024-25 का बजट
20440 करोड़ रुपए
2025-26 का बजट
22234 करोड़ रुपए

कैलाश विजयवर्गीय- मंत्री

2024-25 का बजट
16744 करोड़ रुपए
2025-26 का बजट
18744 करोड़ रुपए

राकेश सिंह-पीडब्ल्यूडी मंत्री

2024-25 का बजट
10175 करोड़ रुपए
2025-26 का बजट
13643 करोड़ रुपए

प्रह्लाद पटेल-पंचायत मंत्री

2024-25 का बजट
27869 करोड़ रुपए
2025-26 का बजट
32329 करोड़ रुपए

विश्वास का बजट

हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट है। हमारे पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने भी विकसित मप्र-2047 का विजन रखा है। यह बजट उस संकल्प को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

तेरा तुझको अर्पण...

जितना पैसा केंद्र से आया, वही ईमानदारी से जनता पर खर्च किया है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा वाली नीति पर काम किया है। यह विकास का बजट है। जनता का बजट है। जनता के लिए है।

जागदीश देवड़ा, वित्त मंत्री

जनता से छलावा

मध्यप्रदेश की जनता को फिर छला गया है। बजट में विकास की कोई ठोस योजना नहीं है, बल्कि इसे कर्ज बढ़ाने, कमीशनखोरी को संस्थागत करने और भ्रष्टाचार को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है।

जीतू पटवारी, प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस

सर्वस्पर्शी बजट

बजट में किसान, श्रमिक, युवा, महिला, समेत हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी ये बजट मध्य प्रदेश के विकास को नई गति देगा। बटज में सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है।

वीडी शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष,भाजपा

विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत बजट सर्वसमावेशी और दूरदर्शी है। यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

राजेंद्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री

सरकार ने मध्यप्रदेश सहित 9 राज्यों से खरीदी 131 हजार टन तुअर

पीएसएस के तहत 89219 किसानों को हुआ फायदा

भोपाल। केंद्र सरकार ने ससंद में देशभर में दलहन फसलों की सरकारी खरीद से जुड़ी जानकारी साझा की। कृषि मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने मूल्य समर्थन योजना के तहत अब तक 1,31,000 टन तुअर की खरीद की है। इससे 89,219 किसान को फायदा हुआ। 2024-25 खरीफ सीजन के लिए पीएसएस के तहत, मंत्रालय ने नौ राज्यों - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से कुल 13.22 लाख टन तुअर की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में तुअर की खरीद शुरू हो चुकी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 11 मार्च तक इन राज्यों में कुल 1.31 लाख टन तुअर (अरहर) की खरीद की गई है। अन्य राज्यों में भी तुअर की खरीद जल्द ही शुरू होगी। सहकारी समितियों नाफेड और एनसीसीएफ के ई-समृद्धि पोर्टल पर पहले से पंजीकृत किसानों से भी तुअर की खरीद की जाती है। मालूम हो कि मूल्य समर्थन योजना तब लागू होती है, जब कुछ कृषि वस्तुओं के बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाते हैं। यह योजना किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करके सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें बाजार की अस्थिरता और मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके। तुअर के अलावा, मंत्रालय ने 2024-25 खरीफ सीजन के लिए 9.40 लाख टन मसूर और 1.35 लाख टन उड़द की खरीद को मंजूरी दी है। बजट 2025 में सरकार ने देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से 2028-29 तक राज्य के उत्पादन के लिए 100 प्रतिशत तुअर, मसूर और उड़द की खरीद की घोषणा की है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मध्यप्रदेश का बजट पेश किया। इस बजट में राज्य के गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी (ज्ञान) सहित सभी वर्गों की बेहतरी के संकल्प को पूरा किया गया है। चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई लाड़ली बहना योजना की राशि बजट में बढ़ाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हालांकि, प्रदेश की लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ने की घोषणा की गई है। इसके अलावा लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम जीवन सुरक्षा योजना से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ और श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ का प्रावधान किया गया है। युवा कल्याण के लिए 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति, खेल और विदेश में पढ़ाई का प्रावधान किया। वित्त मंत्री ने एक घंटे 32 मिनट के भाषण में सबसे बड़ी घोषणा युवाओं को लेकर की।

मोहन सरकार के कार्यकाल का दूसरा सबसे बड़ा बजट

'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा

- भोपाल-इंदौर मेट्रो के लिए 850 करोड़ का प्रावधान
- व्यापमं समेत तीन फ्लाइओवर 139 करोड़ से बनेंगे
- वित्त मंत्री बोले-2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तय किया
- धार में डायनासोर जीवाश्म और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे
- मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 18669 करोड़ों रुपए
- एफ टाइप श्रेणी के शासकीय आवासों के अनुरक्षण के लिए 200 करोड़
- हर विधानसभा में एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा
- गरीबों को अनाज के लिए 7132 करोड़ का प्रावधान किया
- सिंहस्थ के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया
- मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी
- धान बोनस के लिए 850 करोड़ का प्रावधान किया गया
- किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़ का प्रावधान
- संबल योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया
- मध्यप्रदेश के किसानों को शून्य ब्याज पर लोन दिया जाएगा
- पीएम ग्राम सड़क में नई योजना क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण होगा
- उज्जैन हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा
- जल जीवन मिशन के लिए 17135 करोड रुपए का प्रावधान किया
- 5 वर्ष में 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर निर्मित किए जाएंगे
- इस वर्ष 3500 किमी नई सड़क और 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा

कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत 447 करोड़ का प्रावधान

किसान के साथ गांव-गाय का भला

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 105 करोड़

देवड़ा ने कविता से बजट भाषण की शुरुआत...**यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है...जनता और जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सकें हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं।**

भोपाल। जागत गांव हमार

देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। बजट में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाने की घोषणा भी की गई है। उन्होंने बताया कि हमने 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बेस्ड प्रक्रिया से तय किया है। सरकार का लक्ष्य है विकसित मध्यप्रदेश। इसका अर्थ है कि जनता का जीवन खुशहाल हो। महिलाओं को आत्मगौरव मिले। प्रदेश में 5 साल में एक लाख किमी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में निवेश के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं। एक जिला-एक उत्पाद पर फोकस रखा जाएगा। सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। 50 छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी सरकार। गरीबों को अनाज के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।

तीन लाख नौकरी

प्रदेश में 14500 एकड़ भूमि पर 39 नए और क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। इससे 3 लाख रोजगार के अवसर बनेंगे। प्रदेश में 10000 स्टार्टअप स्थापित होने की संभावना है। आगामी 5 वर्षों में उद्योगों को लगभग 30000 करोड़ के इनसेंटिव दिए जाना संभावित है। इस वर्ष उद्योगों को दिए जाने वाले इनसेंटिव के लिए 3250 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

22 नए हॉस्टल बनेंगे

जनजातीय बोल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। नागरिकों के लिए बीमा समिति का गठन होगा। 22 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से 3 लाख रोजगार मिलेंगे। 22 नए आईटीआई कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नारी शक्ति के लिए 26797 करोड़

सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2 लाख 1 हजार 282 करोड रुपए रखे गए। बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और ना ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया। आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3729 करोड रुपए का बजट रखा गया है। नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए 26797 करोड़ का बजट रखा है। मछुआ समृद्धि योजना में 145 करोड़ का प्रावधान।

38 सड़कों का होगा निर्माण

राजधानी भोपाल की बेहद व्यस्ततम सड़क लिंक रोड नंबर-1 के व्यापमं चौराहे पर 53 करोड़ से पौन किमी लंबा नया फ्लाइओवर बनेगा। भोपाल-इंदौर स्टेट हाईवे पर फंदा के पास भी 37.70 करोड़ और सूखी सेवनिया के पास 48.58 करोड़ रुपए से दो नए फ्लाइओवर बनाए जाएंगे। बजट में इन तीनों फ्लाइओवर को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए से 38 सड़कों का निर्माण भी होगा।

कृष्ण पाथेय पर खर्च होंगे दस करोड़

भगवान श्रीकृष्ण ने उज्जैन, मेवात, मालवा-निमाड़, गुजरात, राजस्थान की यात्राएं भी की। यह क्षेत्र पाथेय योजना में शामिल होंगे। इसका एक नक्शा भी तैयार हो रहा है। बजट में इस योजना के लिए सरकार ने दस करोड़ रखे है। योजना का केंद्र उज्जैन का सांदिपनी आश्रम होगा। यहां पर भगवान श्रीकृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील के नारायणा गांव को श्रीकृष्ण, सुदामा मैत्री स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट में राम पथ गमन और चित्रकूट के लिए भी 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मेट्रो के लिए साढ़े 8 सौ करोड़

बजट के बाद मेट्रो की ब्लू लाइन (भदभदा से रत्नागिरी तक) का काम भी शुरू हो सकेगा। भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए सरकार ने बजट में साढ़े 8 सौ करोड़ रुपए का बजट रखा है।

मोहन सरकार ने किस विभाग को कितना दिया बजट

कुंवर विजय शाह	जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति, भोपाल गैस त्रासदी	15073.19 करोड़
करण सिंह वर्मा	राजस्व विभाग	11,105.94 करोड़
संपतिया उइके	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	20,017.04 करोड़
तुलसी सिलावट	जल संसाधन विभाग	9196.21 करोड़
एदल सिंह कंषाना	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	11100.12 करोड़
निर्मला भूरिया	महिला एवं बाल विकास	26797.66 करोड़
गोविंद सिंह राजपूत	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त। संरक्षण	3505.71 करोड़
विश्वास सारंग	खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता	2730.2 करोड़
नारायण कुशवाह	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण	5196.2 करोड़
नागर सिंह चौहान	अनुसूचित जाति कल्याण	2529.13 करोड़
प्रद्युम्न सिंह तोमर	ऊर्जा विभाग	18526 करोड़
राकेश शुक्ला	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	480.74 करोड़
चैतन्य काश्यप	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	1785.95 करोड़
इंदर सिंह परमार	उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा	8275.52 करोड़
कृष्णा गौर	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	1784.66 करोड़
धर्मेंद्र सिंह लोधी	संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास	1611.23 करोड़
दिलीप जायसवाल	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	157.51 करोड़
लखन पटेल	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	2480.98 करोड़
नारायण सिंह पंवार	मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास	332.17 करोड़

मछुआ कल्याण

-मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के अंतर्गत 146 करोड़ का प्रावधान
-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 105 करोड़
-मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला के अंतर्गत 57 करोड़

नवीकरणीय ऊर्जा

-प्रदेश में 11 आयुर्वेदिक कॉलेज, 22 नए आईटीआई खुलेंगे
-अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 7,132 करोड़ रुपए
-विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों के अंतर्गत 5,000 करोड़

किसानों का होगा कल्याण

» अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 13909 करोड़ का प्रावधान
» 5 एचपी के कृषि पम्पोंवं एक बत्ती कनेक्शन के लिए 5299 करोड़
» मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5220 करोड़
» प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2001 करोड़
» मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता के अंतर्गत 1000 करोड़
» अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द के अंतर्गत 518 करोड़ का प्रावधान
» फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी के अंतर्गत 380 करोड़
» सब मिशन ऑन फार्म वॉटर मैनेजमेंट के अंतर्गत 350 करोड़
» नेशनल मिशन ऑन एडिबल आइल एवं आइलसीड के लिए 183 करोड़
» जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि जबलपुर को ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत 120 करोड़ का प्रावधान
» राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि, ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत 78 करोड़
» जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय पेंशन योजना के अंतर्गत 75 करोड़
» सहायक भूमि संरक्षण कार्यालय के अमले की स्थापना के लिए 58 करोड़ का प्रावधान
» समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन पर बोनस के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान
» मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 850 करोड़
» राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 275 करोड़
» ट्रेक्टर, कृषि उपकरणों पर अनुदान के लिए 230 करोड़
» आत्मा परियोजना के अंतर्गत 70 करोड़ का प्रावधान

योजनाओं के लिए बजट

11,000: करोड़ रुपए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
21,000: करोड़ पीएम रोजगार सृजन योजना शहरी
1,000: करोड़ रुपए प्रधानमंत्री कृषि यंत्र योजना
4 960: करोड़ सड़क विकास परियोजना मेट्रो
850: करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
850: करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
720: करोड़ रुपए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना
700: करोड़ सड़क पुल निर्माण योजना
594: करोड़ रुपए नियमित आदिवासी योजना
505: करोड़ निःशक्तजन कल्याण योजना
500: करोड़ रुपए खेलो इंडिया योजना

गायों के लिए खोला खजाना

-गौशालाओं में पशु आहार के लिए प्रति गोवंश प्रतिदिन 20 रुपए को दोगुना कर 40 किया जा रहा है।
-गौ संवर्धन और पशुओं का संवर्धन योजना के लिए 505 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
-कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 58, 257 करोड रुपए का बजट, गत वर्ष से 13409 करोड़ रुपए अधिक का प्रावधान।
-किसानों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण के लिए 694 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
-कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को प्रदेश में लागू किए जाने उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय।
-अप्रैल से सातवें वेतनमान के सुसंगत स्टारों के अनुसार महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण करेंगे।
-राष्ट्रीय उद्यान व बफर क्षेत्र में वन्य जीव वन्य प्राणी मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किमी सीमा में फेंसिंग की जाएगी।
-सुगम परिवहन सेवा होगी प्रारंभ, गांवों को सस्ता और सुलभ परिवहन होगा उपलब्ध, इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान
-नया वाहन खरीदने पर मोटरयान कर में परिवहन वाहन के लिए 15 और गैर परिवहन वाहन के लिए 25 फीसदी की छूट।
-गृह विभाग के लिए 12876 करोड़ रुपए का बजट रखा गया जो गत वर्ष की तुलना में 1585 करोड़ अधिक है।
चार जेलों का निर्माण, नई बैरक निर्माण कर क्षमता वृद्धि की जा रही है। जेल विभाग के लिए 794 करोड़ का प्रावधान।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति

» सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन के लिए 625 करोड़
» रसोई गैस सहायता योजना (उज्ज्वला) के अंतर्गत 262 करोड़
» रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्ज्वला) के लिए 180 करोड़

सड़कों का विस्तार

» मप्र सड़क विकास निगम, सड़कों का निर्माण के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
» ग्रामीण सड़कों, अन्य जिला मार्गों के निर्माण के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान
» मप्र सड़क विकास निगम (एनडीबी) के अंतर्गत 1450 करोड़
» मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (एडीबी) के अंतर्गत 1315 करोड़
» केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 1150 करोड़

सहकारिता के लिए

» सहकारी बैंकों को अंशपूंजी के अंतर्गत ?1000 करोड़ का प्रावधान
» सहकारी बैंकों से कृषकों को ऋण पर ब्याज अनुदान के अंतर्गत 694 करोड़
» प्राथमिक साख सहकारी समितियों को अनुदान के अंतर्गत 149 करोड़
» आडिट बोर्ड के अंतर्गत 72 करोड़
» स्थापना व्यय के अंतर्गत 71 करोड़

जल से समृद्ध मप्र

» बांध तथा संलग्न कार्य के अंतर्गत 3930 करोड़ का प्रावधान
» कार्यपालिक स्थापना के अंतर्गत 1225 करोड़
» नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य के अंतर्गत 1061 करोड़
» केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत 700 करोड़

दर्शक दीर्घा में शिवराज

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर बजट भाषण सुनते नजर आए। इसकी जानकारी जैसे ही सीएम डॉ. मोहन यादव को लगी तो उन्हें बजट भाषण पढ़ रहे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को रोककर शिवराज सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर आभार जताया।

कुपोषण मिटाने पर जोर

बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान को लागू किया जाएगा। इससे 259 विकासखंडों के 11377 गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इससे 19 लाख जनजातीय परिवारों समेत 94 लाख परिवार लाभांवित होंगे। 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

618 करोड़ के फायदे का बजट

राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, जो पिछले साल की तुलना में 15 फीसदी अधिक है। इस साल सरकार को 618 करोड़ का राजस्व सरप्लस रहने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि उसकी कमाई उसके खर्च से ज्यादा होगी। सरकार को कुल 2,90,879 करोड़ की आमदनी होने का अनुमान है। जिसमें राज्य को अपने कर स्रोतों से 1,09,157 करोड़, केंद्र से करों के हिस्से के 1,11,662 करोड़, अन्य गैर-कर मदों से 21,399 करोड़ और केंद्र से मिलने वाली सहायता के रूप में 48,661 करोड़ राजस्व के रूप में मिलने का अनुमान है।

स्वस्थ नागरिक, सशक्त प्रदेश

-चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नयन के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान
-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण के अंतर्गत 196 करोड़
-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण के लिए 171 करोड़ का प्रावधान
-एनयूएचएम/एनआरएचएम के अंतर्गत 4,418 करोड़ का प्रावधान
- मेडिकल कॉलेज और संबद्ध चिकित्सालय के अंतर्गत 2457 करोड़
-जिला /सिविल अस्पताल और औषधालय के अंतर्गत 2140 करोड़
-स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना व संचालन के अंतर्गत 1935 करोड़

गरीबों के लिए नई योजना

» सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए चार हजार 66 करोड़ प्रस्तावित किए गए
» गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए समग्र परिवार योजना शुरू होगी
» मप्र की शालाओं के उन्नयन के लिए 228 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया
» जनजाति छात्रों के लिए आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रस्ताव

भाषण की मुख्य बातें

» जीआईएस के कारण 21 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे
» प्रदेश के जिलों के 19 उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका
» स्टार्टअप नीति 2025 के तहत 10 हजार स्टार्टअप स्थापित होंगे
» उद्योगों को 3250 करोड़ की सहायता दी जाना प्रस्तावित
» स्टार्टअप के तहत 10 हजार स्टार्टअप स्थापित होने का अनुमान
-» 5 वर्षों में उद्योग को 20 हजार करोड़ का इंसेटिव दिया जाएगा

खास बातें

» मध्य प्रदेश की जीडीपी 22 साल में 17 गुना बढ़ी
» बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए काउंसिल का गठन
» 25-26 को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया
» 39 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों को विकासित किया जा रहा

पंचायतों को 6,007 करोड़ का अनुदान

पंचायतों के विकास और वित्तीय मजबूती के लिए 6,007 करोड़ के अनुदान की घोषणा की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2,507 करोड़ अधिक है। साथ ही, ग्राम स्वराज अभियान में 238 करोड़ और अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली अनुदान में 2,041 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बजट में शहर से लेकर गांव तक का रखा ख्याल

-मुरैना में प्रथम सोलर पावर स्टोरेज सेंटर बनेगा
-सौलर ऊर्जा पर 19 हजार करोड़ खर्च होंगे
-1700 करोड़ रुपए से सुधरेंगी शहरों की सड़के
-नगरीय अधोरंचना विकास में 18700 करोड़ रुपए खर्च होंगे
-मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का एलान। 100 करोड़ खर्च होंगे
-सीएम केयर योजना के तहत कैंसर चिकित्सा के लिए सुविधाएं दी जाएंगी।
-सीएम केयर योजना के तहत कैंसर चिकित्सा के लिए सुविधाएं दी जाएंगी।
-गंभीर रोगियों को पीएम श्री एंबुलेंस सेवा का लाभ दिया जाएगा।
-विधानसभा में मौजूद खेल मैदानों का उपयोग हेलीपेड के रूप में किया जाएगा
-कौशल विकास के लिए लोकमाता अहिल्याबाई कौशल कार्यक्रम शुरू होगा
-प्रदेश में नौ अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ बनाए जाएंगे
-25 करोड़ की लागत से एक सर्वसुविधा युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा
-अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
-बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे।
-सिंचित क्षेत्र को 100 लाख हेक्टेयर किया
-सिंचाई के लिए 17863 करोड़ प्रस्तावित जाएगा
-सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस साल 24 फीसदी रकम अधिक खर्च होगी
-जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प होगा
-बिजली बिलों में राहत के लिए 5700 करोड़ का प्रावधान किया गया
-350 करोड़ से आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन तैयार होंगे
-नारी सम्मान और नारी कल्याण के लिए सरकार की मदद

क्षेत्रवार बजट

इन्फ्रास्ट्रक्चर	70,515 करोड़
कृषि	39,207 करोड़
महिला बाल विकास	50,333 करोड़
शिक्षा	44,826 करोड़
एससी,एसटी-ओबीसी	23, 798 करोड
रोजगार	4,835 करोड़
संस्कृति संवर्धन	1627 करोड़
सिंचाई	17,863 करोड़
जल जीवन	17,135 करोड़
ऊर्जा	19 हजार करोड़
सामान्य सेवाएं	36,118 करोड़
अन्य सेवाएं	11 हजार 628 करोड़

10 लाख नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य

बजट में पीएम आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 8 लाख 30 हजार आवास निर्मित हो चुके हैं। अगले 5 वर्षों में 10 लाख नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत एक लाख से अधिक आबादी वाले 33 शहरों में जल आपूर्ति और सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है।

डेयरी पशुओं में खनिज मिश्रण का महत्व

डॉ. अभिलाषा सिंह, डॉ. सुलोचना सेन, डॉ. सुमन संत, डॉ. अनीता तिवारी, डॉ. कंचन के वालवड़कर, डॉ. निष्ठा कुशवाह
पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा

डेयरी पशुओं के लिए खनिज मिश्रण उनके सही विकास, दूध उत्पादन, और समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खनिज मिश्रण में विभिन्न सूक्ष्म और प्रमुख खनिज होते हैं, जो पशुओं की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये खनिज पशुओं के शरीर में कई शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं जैसे हड्डियों का निर्माण, पाचन तंत्र का सुचारू रूप से काम करना, और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना।

खनिज मिश्रण में प्रमुख खनिज

कैल्शियम

कैल्शियम हड्डियों और दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण है।
दूध उत्पादन में मदद करता है और शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखता है।
कम कैल्शियम स्तर से रक्त में कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिससे पशु में कैल्शियम की कमी जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

फॉस्फोरस

फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों की मजबूती में मदद करता है।
यह ऊर्जा उत्पादन और प्रोटीन संश्लेषण में भी भूमिका निभाता है।
कमी से हड्डियों में कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द और दूध उत्पादन में कमी हो सकती है।

मैग्नीशियम

यह मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सही कार्य के लिए जरूरी है।
दूध उत्पादन में भी यह सहायक होता है।
मैग्नीशियम की कमी से पशु में तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं।

सोडियम और पोटैशियम

ये खनिज शरीर के पानी के संतुलन को बनाए रखने और तंत्रिका क्रियाओं को सही ढंग से संचालित करने के लिए जरूरी हैं।
सोडियम और पोटैशियम की कमी से कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन और पाचन समस्याएँ हो सकती हैं।

जिंक- यह पशु की त्वचा, पाचन तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। जिंक की कमी से त्वचा पर घाव, बालों का झड़ना और सूजन जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

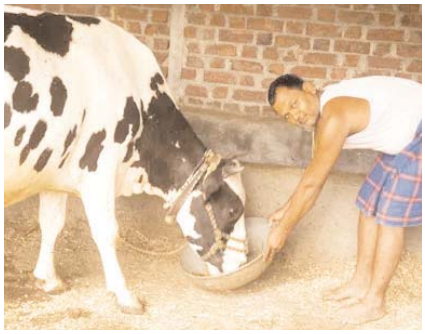

आयरन- आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो ऑक्सीजन परिवहन के लिए आवश्यक है। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे पशु की ऊर्जा में कमी आ सकती है।

कॉपर- यह हेमोग्लोबिन निर्माण में सहायक होता है और तंत्रिका तंत्र के विकास में मदद करता है। कॉपर की कमी से पशु में विकास संबंधी समस्याएँ और रक्तहीनता हो सकती है।

खनिज मिश्रण की आवश्यकता- खनिज मिश्रण को पशु के आहार में शामिल करना आवश्यक है, खासकर उन परिस्थितियों में जब चारा या भोजन में इन खनिजों की कमी हो। यह मिश्रण उनके आहार में कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, और अन्य सूक्ष्म खनिजों का संतुलित अनुपात सुनिश्चित करता है। डेयरी गायों को प्रजनन, स्वस्थ गर्भावस्था और स्वस्थ बछड़ों के जन्म के लिए भी खनिज मिश्रण की आवश्यकता होती है।

खनिज मिश्रण के लाभ- दूध उत्पादन में वृद्धि- खनिजों की उचित आपूर्ति से दूध उत्पादन में वृद्धि होती है और दूध की गुणवत्ता में भी सुधार होता है।

स्वास्थ्य में सुधार- खनिजों की कमी से पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, लेकिन खनिज मिश्रण से यह क्षमता बेहतर होती है।

हड्डियों और दांतों की मजबूती- कैल्शियम और फास्फोरस की सही मात्रा से हड्डियां और दांत मजबूत रहते हैं, जिससे पशु अच्छे से चरते हैं और चोट से बचते हैं।

प्रजनन क्षमता में सुधार- खनिजों की संतुलित आपूर्ति से गायों की प्रजनन क्षमता में सुधार होता है, जिससे उनके गर्भधारण की दर में वृद्धि होती है।

मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के लिए लाभकारी- खनिज मिश्रण से मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है और तंत्रिका तंत्र भी सही तरीके से कार्य करता है।

खनिज मिश्रण का सेवन कैसे करें- खनिज मिश्रण को पशु के भोजन में मिलाकर दिया जाता है। इसे चारे या अन्य आहार के साथ मिश्रित किया जा सकता है।
खनिज मिश्रण की खुराक को सही मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक खनिज सेवन भी हानिकारक हो सकता है।
इसकी खुराक पशु की उम्र, वजन, उत्पादन स्तर और आहार के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। आम तौर पर, यह 50-100 ग्राम प्रति पशु प्रति दिन होता है।
कभी भी अत्यधिक खुराक न दें, क्योंकि इससे अन्य पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ सकता है।
हमेशा गुणवत्ता वाले मिनरल मिक्स्चर का ही उपयोग करें। यह सुनिश्चित करें कि खनिज मिक्सचर में सभी आवश्यक खनिज मौजूद हों। खनिज मिश्रण डेयरी पशुओं के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दूध उत्पादन, प्रजनन क्षमता, हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य, और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए, डेयरी किसानों को अपने पशुओं को संतुलित खनिज मिश्रण देने की आदत डालनी चाहिए।

इंसान के जीवित रहने के लिए जरूरी हैं वन्य-प्राणी

विश्व में अब तक 8590 प्रकार के पक्षियों 2786 प्रकार के स्तनपाई जीवों 5480 प्रकार के सरीसृप वर्ग के जीवो तथा 128 प्रकार के समुद्री स्तनपाई जीवों के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकी है। अनगिनत प्रकार की मछलियां, तितलियां तथा कीड़े मकोड़े इनके अतिरिक्त है।

हिंदुस्तान में 1200 से अधिक प्रकार के पक्षी तकरीबन 500 प्रकार के स्तनपाई जीव अनेक प्रकार के सरीसृप वर्क के जीव तथथा समुद्री स्तनपाई जीव पाए जाते हैं। बेहतरीन जलवायु होने की वजह से जितने प्रकार के अति सुंदर पक्षी हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। उतने अकेले किसी देश में देखने को नही मिलते। इसके अतिरिक्त साइबेरिया एवं अन्य बेहद ठंडे मुल्कों से भी ठंड के प्रकोप से बचने के लिए काफी बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में हमारे यहां आते हैं। ये प्रवासी पक्षी पूर्वी पश्चिमी पहाड़ियों उड़ीसा में चिल्का उद्यान सहित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आकर प्रवास करते हैं। खास बात यह है कि वन्यजीव भारत और अफ्रीका में ही सबसे अधिक और विविध आकार प्रकार के मिलते हैं। हालांकि प्रकृति में प्रजातियां विलुप्त होती रहती हैं। यह सामान्य बात है। लेकिन वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के मुताबिक आज प्राकृतिक विलुप्त की दर से यह 1,000 से 10,000 गुना अधिक है और इसकी अहम वजह है। पशुओं के प्राकृतिक आवासों में द्रुत गति से गिरावट शिकार और उसके साथ क्रूर बर्ताव। यदि प्रजातियों के विलुप्त होने की यही गति रही और इस अनुमान को न्यूनतम भी माने तो धरती पर रहने वाली प्रजातियों में से तकरीबन 200 से 2,000 के बीच प्रजातियां आने वाले समय में पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी। पशुओं के साथ खासकर जंगली जानवरों के साथ क्रूरता की अहम वजह शिकार रही है। वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां तो सिर्फ शिकार की वजह से समाप्त हो गई। यदि भारत की सीमाओं से परे हटकर देखें तो नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक दस सालों के भीतर एक लाख से अधिक अफ्रीकी हाथियों को सिर्फ उनके हाथी दांत की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया। चीन हाथी दांत का सबसे बड़ा उपभोक्ता हैं। वह पर 2018में हाथी दांत पर प्रतिबंध लगा दिया जाने की वजह से हाथियों के शिकार में काफी कमी आई है। वन्य जीवों पर काम करने वाली संस्था ट्रैफिक की एक रिपोर्ट इंडियन वाइल्डलाइफ एमिडस्ट द कोविड-19 क्राइसिस के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान काफी बड़ी संख्या में वन्य जीव के शिकार के मामले सामने आए। शिकार प्रेमी मुगल शासक के शासन काल में सर्वाधिक शिकार होने के कारण वन्य जीवों की संख्या कम हुई, सन् 1600से अनेक देशों में पशु पक्षियों का शिकार बढ़ने से और उसकी तकरीबन 270 प्रजातिया तो हमेशा के लिए समाप्त हो गई, इसके बावजूद भी अनेक देशों में वन एवं वन्य जीव संरक्षण का अभाव बना हुआ है, यदि इन देशों की यही स्थिति रही तो पशु एवं पक्षियों की तकरीबन 500 से अधिक प्रजातियां ओर विलुप्त हो जाएगी। अंग्रेजी शासन से पहले तक काफी बड़े क्षेत्र में वन होने से वन्य जीव बहुत बड़ी संख्या में थे। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि के कारण वनों में वृक्षों का कटना शुरू हुआ उसकी वजह से वन्य जीवों के आवास स्थल छोटे होते होते चले जाने के कारण उनकी संख्या में कमी आना प्रारंभ हो गई। मुगलों और ब्रिटिश शासन काल में शिकार योग्य वन्य जीव काफी बड़ी संख्या में उपलब्ध थे। मुगल शासक तथा राजा महाराजा अपने सेनिको को साथ लेकर धूमधाम से शिकार के लिए निकलते थे। हांका लगाकर तथा घेरा डाल कर वन्यजीवों का शिकार किया जाता था। 19वीं शताब्दी के मध्य से शिकार करने के शस्त्रों में वृद्धि होने। विशेष कर बोर राइफल तथा एक्सप्रेस राइफल के बनने के कारण वन्यजीवों के शिकार एवं संहार में वृद्धि शुरू हुई। अंग्रेज तथा भारतीय अधिकारियों व चाय बागानों के मालिक शिकार के बहुत शौकीन होते थे। ये शिकारी न केवल सिंह, बाघ, तेंदुए, चीते जैसे बड़े वन्य जीवों का बड़े पैमाने पर शिकार करते थे। बस आखेट की हवस व झूठी शान के कारण हिरण, सांभर , जंगली सुअर, लोमड़ी ,खरगोश आदि छोटे जीवों का भी बहुत बड़ी संख्या में शिकार करते थे। शिकार के शौकीनों के कारण अनेक प्रकार की आकर्षक चिड़िया भी भूनें जाने से नहीं बचीं। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में बाघों की भारी संख्या थी,शिकार के कारण व उनकी खाल के काफी मंहगे दामों में बिकने की वजह से यह अत्यंत आकर्षक एवं गौरवशाली जीव का शिकार हुआ।

विदेशों में हिन्दू मंदिरों पर हमले दुर्भाग्यपूर्ण

खालिस्तानी अलगाववादियों से जुड़े कुछ अराजक तत्वों ने एक बार फिर अमेरिका में कैलिफोर्निया स्थित स्वामी नारायण मंदिर पर हमला किया है, हिन्दुओं वापिस भारत जाओ जैसे आपत्तिजनक संदेश लिखकर मंदिर को क्षति पहुंचायी गई है। हिन्दू मन्दिरों एवं आस्था पर बार-बार हो रहे ये हमने दुर्भाग्यपूर्ण एवं शर्मनाक है। आतंक फैलाने की मंशा से मंदिरों पर हमले की ऐसी घटनाओं का बार-बार होते रहना चिन्ता का सबब हैं। ऐसे पृथकतावादी तत्व हिंदुओं के खिलाफ विषवमन करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं एवं दवाब बनाना चाहते हैं। भारतीय सांझा संस्कृति में मिलजुलकर रहने वाले समाजों को विभाजित करके घृणा, नफरत एवं द्वेष उत्पन्न करने वाले तत्वों को न केवल बेनकाब करने की जरूरत है बल्कि उन्हें नेस्तनाबूंद किया जाना चाहिए। बात केवल खालिस्तानी अलगाववादियों की नहीं है, मुस्लिम आतंकवादी भी विभिन्न देशों में हिन्दू धर्म, मन्दिर, आस्था एवं संस्कृति पर ऐसे ही हमले करके दहशत फैला रहे हैं। हिन्दू समुदाय नफरत के खिलाफ मजबूती से खड़ा है, वह कभी भी नफरत को जड़ नहीं जमाने देंगा। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा सरकारों द्वारा ऐसे मामलों की अनदेखी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई न करना विडम्बनापूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण है। भारत सरकार को भी कड़े कदम उठाते हुए सख्त संदेश देना चाहिए। अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाए जाने को खालिस्तान समर्थकों से जोड़कर देखा जा रहा है। दक्षिण कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स इलाके में स्थित मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए और मंदिर को क्षति पहुंचाई गयी। माना जा रहा है कि खालिस्तान जनमत संग्रह से पहले साजिश के तहत ये हमला किया गया है। कुछ दिन पहले न्यूयार्क में भी स्वामीनारायण मंदिर पर भी हमला हुआ था। 25 सितंबर को कैलिफोर्निया के से ामेंटो स्थित स्वामीनारायण मंदिर को भी निशाना बनाया गया था, तोडफ़ोड़ की गई और उस पर आपत्तिजनक संदेश भी लिख दिए गए हैं। आपत्तिजनक यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा में सि य ऐसे तत्वों को इन देशों की सरकारों द्वारा राजनीति के चलते खुला समर्थन देना एवं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर प्रश्रय दिया जाना बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, कब तक खामोश रहा जाए। कैलिफोर्निया में स्वामीनारायण मंदिर पर हुई घटना से पहले लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर के गाड़ी के सामने खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन किया था, जिसे सामान्य घटना नहीं माना जा सकता। जो खालिस्तान समर्थक विदेश मंत्री के काफिले तक कूद गया, वह सुनियोजित ढंग से हमला भी कर सकता था। निश्चित तौर पर यह ब्रिटिश पुलिस की कोताही एवं लापरवाही है। उस समय खालिस्तानी उग्रवादी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का भी अपमान किया। विडंबना यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश की सरकारें ऐसे हमलों व मंदिरों को अपवित्र करने, उनको नुकसान पहुंचाने, अराजक माहौल खड़ा करने की घटनाओं को अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में रखकर आंखें मूंद लेती हैं या कुछ देश कट्टरतावाद के चलते उन देशों के अल्पसंख्यक समुदायों पर तरह-तरह के हमले होने देती है। यह विडम्बना ही है कि जब दूसरे देशों में उनके धर्म के लोगों के पूजा स्थलों पर हमले होते हैं तो उसे धार्मिक आजादी व मानवाधिकारों का संकट बताने लगते हैं।

देश में गेहूं का बंपर उत्पादन होने का जताया गया अनुमान, राज्यों में अब शुरू हो गई खरीदी

गेहूं उत्पादन में यूपी पहले-एमपी दूसरे नंबर पर तीसरे पर पंजाब और चौथे पायदान पर हरियाणा

तापमान के कारण गेहूं उत्पादन और इसकी क्वालिटी पर असर पड़ने की बात कही गई थी

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में इस बार रबी सीजन 2024-25 में गेहूं का बंपर उत्पादन होने का अनुमान है। इस सब के बीच, सरकार ने अब पिछले सीजन यानी 2023-24 में गेहूं के उत्पादन में राज्यों की हिस्सेदारी को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए हैं। केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी की गई लिस्ट में गेहूं उत्पादन में पहले की तरह उत्तर प्रदेश 31.7 प्रतिशत उत्पादन हिस्सेदारी में टॉप पर हैं। मध्य प्रदेश 21.3 उत्पादन हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर है। गेहूं उत्पादन में तीसरे नंबर पर पंजाब (14.7 फीसदी), चौथे पर हरियाणा 10 फीसदी उत्पादन, पांचवें पर राजस्थान 9.6 फीसदी, छठवें पर बिहार 5.9 फीसदी, सातवें नंबर पर गुजरात 3.3 फीसदी उत्पादन, आठवें नबंर पर महाराष्ट्र 1.9 फीसदी, नौवें पर पश्चिम बंगाल 0.6 फीसदी, दसवें नंबर पर हिमाचल प्रदेश 0.5 प्रतिशत उत्पादन, उत्पादन में ग्यारहवें नंबर पर झारखंड 0.4 प्रतशित के साथ है और लिस्ट में आखिरी पायदान पर 0.2 प्रतिशत उत्पादन हिस्सेदारी के साथ 12वें और अंतिम पायदान पर छत्तीसगढ़ है।

ऐसा रहेगा गेहूं उत्पादन

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक, इस बार (सीजन 2024-25 में) देश में 115 लाख टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने अपने आंकड़ों में रकबे में भारी बढ़ोतरी होने के साथ ही रिकॉर्ड बंपर पैदावार होने की बात कही है। कुछ समय पहले मौसम वैज्ञानिकों ने बढ़ते तापमान के कारण गेहूं उत्पादन और इसकी क्वालिटी पर असर पड़ने की बात कही थी।

व्यापारी नकार रहे आंकड़े

सरकार का कहना है कि किसानों ने ज्यादा तापमान सहन करने में सक्षम गेहूं किस्मों की बुवाई की है। अगर थोड़ी बहुत फसल पर असर पड़ता भी है तो रकबा पिछले साल से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में भी उत्पादन पिछले साल से ज्यादा ही होगा। सरकार की ओर से उत्पादन को लेकर पेश किए गए अनुमान से व्यापारी सहमत नहीं है। उन्होंने इन आंकड़ों को नकारते हुए अपने खुद के आंकड़े बताए हैं। लेकिन ट्रेड एनालिस्ट ने उनसे ही सवाल किया कि वे अपने आंकड़े किस आधार पर बता रहे हैं।

मंडियों में नई फसल की आवक शुरू

इस बीच कई राज्यों में गेहूं फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और मंडियों में नई उपज भी पहुंचने लगी है। कई राज्यों में तो 1 मार्च से गेहूं की एमएसपी पर सरकारी खरीद की शुरुआत हुई। हालांकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। सरकार इस बार 2475 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं की खरीद कर रही है। कुछ राज्यों में इसके अलावा प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है।

मप्र में गेहूं के दाम एमएसपी के आसपास यूपी की मंडियों में मिल रहा तगड़ा दाम

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में गेहूं की नई फसल की कटाई शुरू हो गई है और मंडियों में गेहूं की अच्छी आवक बनी हुई है। हालांकि, त्योहार के कारण आवक में थोड़ा अंतर देखने को मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश में तो आज से गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हो गई है, इस बीच ज्यादातर मंडियों में गेहूं की कीमतें एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखने को मिल रही हैं, तो वहीं कुछ मंडियों में दाम एमएसपी से थोड़े नीचे बने हुए हैं। लेकिन, उत्तर प्रदेश में किसानों को गेहूं का बहुत तगड़ा दाम मिल रहा है और बंपर मुनाफे की स्थिति बनी है।

गेहूं उत्पादन में दोनों राज्य शीर्ष पर

गेहूं उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही प्रमुख राज्य हैं और दोनों ही देश के कुल गेहूं उत्पादन की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं उत्पादन की हिस्सेदारी के आंकड़े जारी किए थे, जिसमें एक बार फिर यह स्थिति देखने को मिली। शनिवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में 2,766.10 टन गेहूं की आवक रही। वहीं मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में 474.62 टन आवक दर्ज की गई।

एमपी की मंडियों में गेहूं का ताजा भाव

मंडी	न्यूनतम कीमत (क्विंटल में)	अधिकतम कीमत	औसत कीमत
सैलाना	2475	2475	2475
सनावद	2450	2460	2460
सांवेर	2401	2501	2501
सेंधवा	3170	3170	3170
शाहगढ़	2500	2500	2500
बदनावर	2401	2401	2401
बड़वाहा	2450	2575	2500
बड़वाहा	2450	2500	2500
दालौदा	2460	2500	2500
देवास	2421	2516	2516
धार	2545	2545	2545
गंजबसौदा	2575	2635	2600
इंदौर	2308	2783	2526
इंदौर	2580	2600	2600

यूपी की मंडियों में गेहूं का ताजा भाव

मंडी	न्यूनतम कीमत (क्विंटल में)	अधिकतम कीमत	औसत कीमत
बलिया	2915	2950	2935
बाराबंकी	2940	3020	2980
बस्ती	2700	2910	2860
बुलंद शहर	2950	2970	2960
चोरीचोरा	2275	2650	2350
फैजाबाद	2800	2900	2860
गोंडा	2950	3100	3000
जहांगीराबाद	2920	2950	2935
खैर	2750	2900	2850
खटौली	2800	3500	3200
खुरजा	2910	3000	2960

सरसों के उत्पादन में होगी बड़ी गिरावट, आठ राज्यों ने कराया सर्वे

इधर, केंद्र सरकार ने इस साल 89.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बुवाई और 128.73 लाख टन उत्पादन का अनुमान लागाया है। लेकिन, अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रबी 2024-25 सीजन के लिए रेपसीड-सरसों के रकबे और उत्पादन को लेकर अपने खुद के अनुमान जारी किए है। पूर्वानुमान विश्लेषण के आधार पर, सरसों का कुल रकबा 92.5 लाख हैक्टेयर होने का अनुमान है लगाया है, जबकि एसईए के मुताबिक, 115.2 लाख टन उत्पादन रहने का अनुमान है।

उक्त आंकड़ों में रकबा तो सरकारी आंकड़ों के मुकाबले मामूली रूप से ज्यादा है, लेकिन उत्पादन को लेकर एसईए ने बड़ी गिरावट दिखाई है। हालांकि, एसईए का अनुमानित सरसों फसल रकबा, पिछले साल सरकार की ओर से जारी किए गए 91.8 लाख हेक्टेयर रकबे से कम है,

जो 2.5 प्रतिशत की गिरावट दिखाता है। एसईए के अध्यक्ष संजीव अस्थाना ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत की खाद्य तेल को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ी है। यही वजह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक बनकर उभरा है। इस वजह से देश के खजाने पर तो बुरा असर पड़ ही रहा है, साथ ही किसानों की आय पर भी गंभीर दबाव पड़ा है।

सरसों की कीमतें कम होने की संभावना

संजीव अस्थाना ने कहा कि एक जिम्मेदार और शीर्ष उद्योग निकाय के रूप में एसईए ने तिलहन की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई पहलों की शुरुआत की है। इसी क्रम में एक इनिशिटिव, मॉडल मस्टर्ड फार्म प्रोजेक्ट वर्ष 2020-21 से चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2029-30 तक भारत के रेपसीड-सरसों के उत्पादन को 200 लाख टन तक बढ़ाना है।

आठ राज्यों में सर्वे

आठ राज्यों जैसे असम, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का सर्वेक्षण किया गया। आठ प्रमुख राज्यों के प्राथमिक सर्वेक्षण और शेष राज्यों के द्वितीयक सर्वेक्षण के आधार पर, वर्ष 2024-25 के लिए भारत का रेपसीड-सरसों का रकबा 92.5 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है।

शुओं को हेलीकॉप्टर से शिफ्ट करने की तैयारी

नीलगाय-हिरण से फसलों को बचाएगी सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

देशभर में जंगली जानवरों और बेसहारा पशुओं के कारण फसल खराब होने के मामले बेहद आम है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि जंगली जानवर कई क्षेत्रों में फसल चौपट कर देते हैं। लेकिन, सरकार ने इसे लेकर अब एक योजना बनाई है, जिसके तहत जिन क्षेत्रों में नीलगाय और काले हिरण जैसे जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन समिति की 15वीं आमसभा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में किसानों को जंगली जानवरों से होने वाली फसल नुकसान को रोकने के लिए खास कार्य योजना तैयार की गई है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नीलगायों और काले हिरणों को को पकड़कर अन्य किसी जगह बसाया जाएगा। इन जंगली जानवरों को को पकड़ने के लिए रॉबिन्सन 44 नामक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया जाएगा।

ई-टेंडर जारी किए गए

ई-टेंडर जारी किए गए है। लेकिन तीन बार टेंडर जारी करने के बाद भी अभी तक वांछित हेलीकॉप्टर और अनुभवी पॉयलट का टेंडर के लिए आवेदन नहीं मिला है। इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए रॉबिन्सन 44 हेलीकॉप्टर या इसके समकक्ष विमान उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख सचिव विमानन से अनुरोध किया गया है। हेलीकॉप्टर मिल जाने पर नीलगाय और ब्लैक बक (काले हिरण) को पकड़ने का काम तत्काल शुरू किया जाएगा और किसानों की फसल बचाने में मदद

इंसानों में टकराव रोकने पर जोर

बैठक में सीएमने कहा कि मध्यप्रदेश वन्य जीवों से समृद्ध प्रदेश है। यहां शेर, बाघ, चीता, सांभर, हाथी सभी उपलब्ध हैं। उन्होंने अफसरों से कहा कि वन्य जीवों के कल्याण के लिए सभी कोशिशें की जाएं। प्रदेश के वनों में रह रहे हाथियों के कल्याण की भी चिंता करें और उनके भोजन की व्यवस्था करें। घास के मैदान बनाएं, ताकि वे भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्रों में यहां-वहां न भटकें। इससे किसानों की फसल हानि भी रुकेगी और इंसानों और हाथी के बीच टकराव की स्थिति के स्थान पर साहचर्य की भावना विकसित होगी।

वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा

सीएम ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि मध्यप्रदेश में वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही। इसके लिए जहां बेहतर सुविधा उपलब्ध हो वहां वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर-कम-जू बनाने के लिए केन्द्र सरकार, सेंट्रल जू अथॉरिटी और अन्य वन्य जीव संस्थानों से मार्गदर्शन लेकर इस दिशा में आगे बढ़ें। वन्य जीवों को खुले में देखना पर्यटकों के लिए सदैव सहज आकर्षण का केन्द्र होता है और मध्यप्रदेश में इस दिशा में कार्य कर वन्य जीव पर्यटन को एक नई दिशा की ओर ले जाएं।

-सीएम बोले-वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार संकल्पित

प्रदेश में 12,981 गिद्ध मौजूद, वर्ष में 19 प्रतिशत बढ़ी गिद्धों की संख्या

प्रदेश में बनेंगे दो नए वन्य जीव अभ्यारण्य, सीएम ने दी मंजूरी

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है मध्यप्रदेश में वन्य जीव पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और सरकार दृढ़ संकल्प के साथ वन, पर्यावरण एवं वन्य जीव सहित जलीय जंतुओं के संरक्षण के लिए भी काम कर रही है। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक कदम ओर बढ़ाते हुए अब प्रदेश में दो नए वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए जाएंगे। यह नए वन्य जीव अभयारण्य ओंकारेश्वर एवं जहानगढ़ में स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास में मप्र राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 28वीं बैठक में 2 वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के प्रभावी प्रयासों का ही सुखद परिणाम है कि प्रदेश में बाघ, तेंदुआ, चीता, हाथी, घड़ियाल के साथ-साथ विलुप्त होती प्रजाति के गिद्धों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। गत माह 17 से 19 फरवरी 2025 को हुई ताजा गिद्ध जनगणना के अनुसार प्रदेश में 12 हजार 981 गिद्ध पाए गए हैं। गिद्धों की संख्या बीते वर्ष में ही 19 प्रतिशत बढ़ी है। उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर वन्य जीव अभयारण्य देवास-खंडवा जिले के करीब 614.0709 वर्ग किमी वन रकबे में तथा जहानगढ़ वन्य जीव अभयारण्य श्योपुर जिले के 6.328 वर्ग किमी वन रकबे पर विकसित किया जाएगा। बैठक में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार, वन्य प्राणी बोर्ड के सदस्य विधायक हेमंत खंडेलवाल, मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, चीफ वाईल्ड लाईफ वार्डन, सदस्य मोहन नागर, डॉ. नारायण व्यास, डॉ. सुदेश बाघमारे, डॉ. भटनागर, डॉ. रविचंद्रन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रेस्क्यू सेंटर कम जू की स्थापना में लाएं तेजी

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि उज्जैन जिले के नौलखी में वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर कम जू प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने इस सेंटर की स्थापना की प्रगति की जानकारी ली और इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू सेंटर कम जू को वन्य जीव पर्यटन के लिहाज से तैयार किया जाए। बैठक में बताया गया कि उज्जैन की तरह एक वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर कम जू का निर्माण जबलपुर जिले में भी प्रस्तावित है। सीएम ने कहा कि मप्र वन्य जीवों की विविधता से भरा राज्य है। यहां के मंदसौर, नीमच, शिवपुरी समेत चंबल के जिलों में बड़ी संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को वन्य जीवों के संरक्षण के निर्देशित करते हुए कहा कि मगरमच्छ सड़कों एवं आबादी क्षेत्र में न पहुंचे, इसके लिए उन्हें खाली पड़ी नदियों में पुनर्स्थापित किया जाए। वन्य जीवों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर कार्यशालाएं एवं संयुक्त बैठक आयोजित की जाएं। देश-दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वन्य जीवों के संरक्षण को पर्यटन से जोड़ते हुए परियोजना तैयार करने की आवश्यकता है।

कल्याण की करें चिंता

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीव पर्यटन बोर्ड थलचर (वनचर), जलचर और नभचर तीनों श्रेणियों के जीव-जंतुओं, पशु-पक्षियों एवं वन्य प्राणियों के कल्याण की चिंता करे। यह सभी प्राणी हमारी वृहद जैव विविधता की धरोहर हैं। हमें इन्हें बचाना है, इनके विकास के लिए अनुकूलित वातावरण उपलब्ध कराना है।

गैडें बसाने की तलाशें संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने टाइगर, चीतों एवं घड़ियालों का घर बन चुके मध्यप्रदेश में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से गैंडों को लाने और साऊथ अफ्रीका से जिराफ को लाकर यहां बसाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। मध्यप्रदेश में मौजूद पर्यटन स्थलों एवं वन्य जीव अभयारण्यों के आकर्षक वीडियो तैयार कर प्रसारित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय बंधु वनों के प्राकृतिक संरक्षक है।

30 विकास प्रस्तावों का अनुमोदन

मुख्यमंत्री ने वन्य प्राणी बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किए गए 33 विकास प्रस्तावों में से 30 विकास प्रस्तावों का अनुमोदन किया। उल्लेखनीय है कि वन्य जीव पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसी वर्ष 17 फरवरी को राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में 10 घड़ियाल को चंबल नदी में छोड़ा था। इससे पहले 5 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 5 वयस्क चीते कूनो नेशनल पार्क में छोड़े।

प्याज निर्यात पर 20% शुल्क उत्पादन में देखी गई भारी बढ़त

भोपाल। जागत गांव हमार

भारतीय बागवानी उत्पाद निर्यातक संघ और इसके सदस्य, जो प्याज निर्यात क्षेत्र में प्रमुख हितधारक और सक्रिय खिलाड़ी हैं, प्याज निर्यात पर वर्तमान 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क के विनाशकारी प्रभावों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह जल्द से जल्द इस शुल्क को हटाने के लिए कदम उठाए, ताकि भारत के प्याज निर्यात क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जा सके और इस क्षेत्र के किसानों और उद्योग को लाभ मिल सके। भारत में प्याज उत्पादन में वृद्धि देखी गई है, विशेषकर देर से खरीफ और रबी दोनों मौसमों में। 2024-25 की उत्पादन वर्ष में, देर से खरीफ फसल में रकबे में 26.5 प्रतिशत (2.10 लाख हेक्टेयर बनाम 1.66 लाख हेक्टेयर) की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे उत्पादन में भी 26.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है (29.65 लाख टन बनाम 23.44 लाख टन)। रबी फसल में भी उत्पादन में भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। अनुमानित रकबा 20.14 प्रतिशत (13.00 लाख हेक्टेयर बनाम 10.82 लाख हेक्टेयर) बढ़ा है, जबकि उत्पादन में 29.3 प्रतिशत का इजाफा होने का अनुमान है (247 लाख टन बनाम 191 लाख टन)। यह वृद्धि यह संकेत देती है कि भारत में प्याज का उत्पादन अधिक हो रहा है, जिससे बाजार में अधिशेष हो सकता है। ऐसे में निर्यात शुल्क जारी रखने से, न केवल हम इस अनुकूल उत्पादन परिदृश्य का लाभ उठाने से चूकेंगे, बल्कि भारत के लिए संभावित विदेशी मुद्रा आय का भी नुकसान होगा। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वह इस विषय को गंभीरता से लेकर, उच्च निर्यात शुल्क को हटाने के लिए जल्द कदम उठाए। इससे न केवल प्याज निर्यात क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जा सकेगा, बल्कि भारत को दुनिया में एक अग्रणी प्याज निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को भी फिर से स्थापित किया जा सकेगा। हमें विश्वास है कि आपका समय पर हस्तक्षेप प्याज निर्यात क्षेत्र की दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और भारतीय किसानों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेगा।

निर्यात शुल्क का प्रभाव

भारत के प्याज निर्यात पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क का वर्तमान प्रभाव अत्यधिक नकारात्मक रहा है। उच्च शुल्क ने हमारे प्याज के निर्यात को प्रभावित किया है और हमें वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता खोने का खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान जैसे प्रतिस्पर्धी देशों ने इस स्थिति का फायदा उठाया है, और अब वे हमारी कीमत पर वैश्विक प्याज निर्यात बाजार में बड़ा हिस्सा हासिल कर रहे हैं। अप्रैल से दिसंबर 2023-24 के दौरान हमारे प्याज निर्यात में 51.8 की भारी गिरावट आई है। 2022-23 की इसी अवधि में 17.44 लाख टन प्याज निर्यात किए गए थे, जबकि 2023-24 में यह आंकड़ा सिर्फ 8.41 लाख टन रह गया। यह गिरावट निर्यात क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है और इसे तत्काल ठीक किया जाना चाहिए।

निर्यात शुल्क हटाने के फायदे

खोया हुआ बाजार हिस्सा वापस मिलेगा: उच्च निर्यात शुल्क की वजह से हम अपना अंतरराष्ट्रीय बाजार खो चुके हैं, लेकिन शुल्क हटाने से हम अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बहाल कर सकते हैं और फिर से वैश्विक प्याज निर्यात बाजार में प्रमुख स्थान हासिल कर सकते हैं। किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति: निर्यात शुल्क हटने से किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य मिल सकेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

संभावित संकट बिक्री को रोका जा सकेगा: उच्च निर्यात शुल्क के कारण उत्पादों का अधिशेष हो सकता है, जिससे किसानों को संकट में पड़कर अपने उत्पादों को नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है। शुल्क हटाने से इस संकट को टाला जा सकता है।

कृषि क्षेत्र में समग्र विकास: निर्यात शुल्क हटाने से कृषि क्षेत्र में समग्र विकास होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारतीय किसानों को वैश्विक बाजारों में अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।

किसान पाटीदार का दावा-सालभर में करीब 40 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट कमाएंगे

55 लाख खर्च कर बनाया पॉली हाउस बिना मिट्टी उगा रहे चाइनीज खीरा

मंदसौर में तीन दोस्तों ने लोन लेकर बनाया पॉली हाउस, चार महीने में कमाए 11 लाख

मंदसौर। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के गरोठ में तीन दोस्त मिलकर बिना मिट्टी के चाइनीज खीरा उगा रहे हैं। उन्होंने 2 बीघा जमीन से इसकी शुरुआत की है। इसके लिए 42 लाख रुपए लोन भी लिया। पिछले चार महीने में 11 लाख रुपए का मुनाफा कमा चुके हैं। **जागत गांव हमार** के इस अंक में अपने पाठकों को मंदसौर के बोलिया नगर इलाके के युवा किसानों की उपलब्धि बता रहे हैं। यहां रहने वाले दीपक पाटीदार, मोहम्मद आदिल अफगानी और मोहित पाटीदार आपस में दोस्त हैं। तीनों ही पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इन्होंने हाइड्रोपोनिक सॉइल तकनीक के जरिए चाइनीज खीरा उगाया है। दावा है कि सालभर में करीब 40 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट कमाएंगे। तीनों दोस्त चाइनीज खीरा की सफलता को देखते हुए अब शिमला मिर्च को भी इसी तकनीक से उगाने पर काम कर रहे हैं।

किसान दीपक पाटीदार बताते हैं कि पहले पारंपरिक खेती के जरिए गेहूं समेत अन्य फसलें उगाते थे, लेकिन मुनाफा नहीं था। कई बार तो लागत भी नहीं निकल पाती थी। करीब एक साल पहले यूट्यूब पर वीडियो देखा। इसमें हाइड्रोपोनिक तकनीक के बारे में पता चला। तीनों दोस्तों ने मिलकर प्रयोग के तौर पर इसी तकनीक से खेती करने के बारे में सोचा। कृषि विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। गुजरात के गांधीनगर भी गए। पता चला कि मिट्टी वाली पद्धति से साल

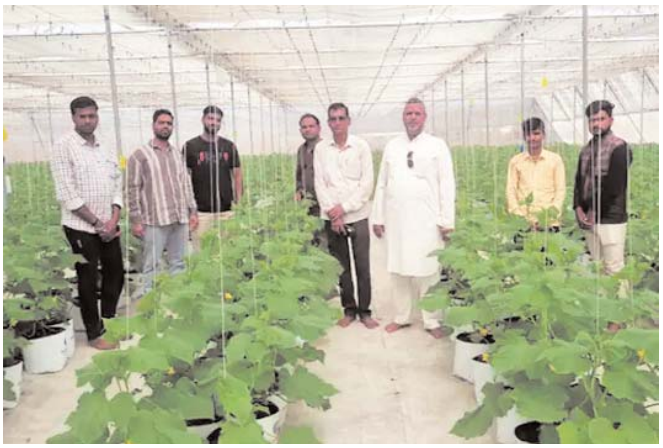

में दो ही फसल ले सकते हैं। वहीं, हाइड्रोपोनिक सॉइल टेक्निक से एक साल में तीन फसल ली जा सकती हैं। इस तकनीक से उत्पादन भी ज्यादा होता है। फंगस और अन्य रोग भी हावी नहीं होते।

इसके बाद पॉली हाउस के लिए 42 लाख का लोन लिया। कुल 55 लाख खर्च किए। यहां ग्रीन हाउस लगाया। शासन से मिलने वाली 25 लाख की सब्सिडी से पॉली हाउस लगाने का हौसला आया। हाइड्रोपोनिक सॉइल तकनीक से बिना मिट्टी के खीरे की खेती शुरू की। महज चार महीने में 11 लाख रुपए की आमदनी हुई।

सालाना 40 लाख आमदनी की उम्मीद- दीपक पाटीदार ने बताया कि इस तकनीक से एक साल में तीन बार खीरे का उत्पादन ले सकते हैं। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, तो साल में 30 से 40 लाख से ज्यादा की आमदनी हो जाएगी।

अब लाल-पीली शिमला मिर्च उगाने की प्लानिंग

किसान मोहित पाटीदार ने बताया कि पहली बार में पानी का पीएच मेंटेन नहीं कर पाए, जिससे उत्पादन कुछ कम हुआ है। पहली बार में करीब 40 टन उत्पादन हुआ है। दूसरी फसल करीब 50 से 60 टन होने का अनुमान है। अगर बाजार मूल्य 25 किलो भी मिलते हैं, तो 15 लाख की आमदनी हो जाएगी। मोहित ने कहा- ग्रीन हाउस के लिए हमें कुछ परेशानी हुई। इसके लिए आदिल के पिता मोहम्मद सलीम अफगानी से मिले, उनको प्रोजेक्ट समझाया। बहुत समझाने के बाद वे तैयार हुए। उनकी जमीन पर ही यह प्रोजेक्ट तैयार किया। हमारी खेती की तकनीक स्मार्ट और नई है। अब हम आगे 4 एकड़ जमीन में दो ग्रीन हाउस लगाने का प्लान कर रहे हैं। इसमें लाल और पीली शिमला मिर्च लगाने की तैयारी है। अगर कोई इसे सीखना चाहता है, तो हम उनकी मदद करेंगे।

पिता बोले- सोचा था, कर्ज में डूब जाएंगे

आदिल अफगानी के पिता मोहम्मद सलीम अफगानी बताते हैं कि बच्चों ने बिना मिट्टी के खेती करने की बात कही, तो मैं अचंभे में पड़ गया। मुझे लगा कि ये बच्चे कर्ज में डुबो देंगे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि बच्चों ने अच्छी राह चुनी है। खेती करके ये लोग अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।

नर्मदापुरम जिले की इटारसी के सुधीर वर्मा ने किया कमाल

आठ एकड़ में गुलाब की खेती, सालाना 20 लाख हो रही कमाई

भोपाल। जागत गांव हमार

वैसे तो गुलाब के फूलों की डिमांड सालभर बनी रहती है, लेकिन खासकर तीज-त्योहारों पर डिमांड में भारी ज्यादा उछाल आ जाता है। साथ ही दाम भी महंगे हो जाते हैं, जिससे मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। आम दिनों में भी गुलाब के फूल की कीमत सामान्य फूलों के मुकाबले ज्यादा होती है, इसलिए इसकी खेती बहुत ही फायदेमंद होती है। आज हम आपको एक ऐसे किसान की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने 23 साल पहले पारंपरिक खेती से अलग हटकर गुलाब की खेती शुरू की और आज वह और उनका परिवार गुलाबा से सालाना 20 लाख रुपए कमा रहा है। सफलता की यह कहानी मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले की इटारसी तहसील के तीखड़ गांव के रहने वाले किसान सुधीर वर्मा की है। वर्तमान में वह 8 एकड़ खेत में गुलाब की खेती करते हैं और उनके करीब 800 ग्राहक

फिक्स हैं, जो उनसे फूल खरीदते हैं। सुधीर को गुलाब की खेती से फायदा होता देख आसपास के क्षेत्र के अन्य किसान भी गुलाब की खेती करने लगे हैं।

गेहूं-सोयाबीन से कम होता था मुनाफा- सुधीर ने बताया कि वह गुलाब की खेती से पहले गेहूं और सोयाबीन की खेती करते थे, जिससे उन्हें प्रति एकड़ सिर्फ 35 हजार रुपए की कमाई ही होती थी। साल 2001 की बात है, जब उन्होंने कृषि अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने फूलों की खेती की जानकारी दी और मामला जम गया। इसके बाद उन्होंने विभाग की मदद से फूलों की खेती की तकनीक सीखी।

सीमैप से ट्रेनिंग ली - सुधरी ने नोएडा के आईआईएचटी और लखनऊ के सीमैप से ट्रेनिंग ली और खेती की शुरुआत पहले दिल्ली, कोल्हापुर, नागपुर समेत कई शहरों में खेती देखी। वहीं, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अमृत गार्डन (पूर्व में मुगल गार्डन) और नागपुर एनआरसीसी से फूलों की खेती की तकनीक सीखी। महाराष्ट्र के सांगली और सतारा में भी खेती का प्रशिक्षण लिया।

शुरुआत में 13 गुलाब के पौधे लगाए- 2001 में 13 गुलाब के पौधों के साथ खेती शुरू की। आज वह 8 एकड़ खेत में गुलाब के फूल उगाते हैं और खुद ही गुलाब जल बनाकर बाजार में बेचते हैं, जिससे सालाना 20 लाख आय हो रही है। उन्होंने 8 लोगों को रोजगार भी दिया है, जो उनके खेत में काम करते हैं। सुधीर ने बताया कि अगर फूल नहीं बिक पाते हैं तो इनसे गुलाब जल तैयार किया जाता है। 10 किलो गुलाब से 5 लीटर गुलाब जल बनता है और एक लीटर गुलाब जल 300 रुपए में बिकता है। वह इसे मुंबई और गुजरात में भी सप्लाई करते हैं।

20 साल पहले गुलाब जल की मशीन खरीदी

20 साल पहले दिल्ली से गुलाब जल बनाने की मशीन खरीदी थी। उस समय राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में सीमैप लखनऊ ने प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें गुलाब जल की अलग-अलग मशीनें भी दिखाई गईं, तब उन्होंने 65 हजार में मशीन खरीदी थी। मशीन से आज भी उन्हें फायदा हो रहा है। सुधीर ने कहा कि वैसे तो गुलाब का पौधा एक महीने में फूल देने लगता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की पैदावार के लिए 6 महीने का समय लगता है। गुलाब की खेती के लिए जल्दी पानी छोड़ने वाली मिट्टी की जरूरत रहती है। रेत मिट्टी और रेतीली मिट्टी इसके लिए बेस्ट मानी जाती हैं। अच्छी देखभाल करने पर गुलाब की फसल 7 से 8 साल तक पैदावार देती है। ठीक से देखरेख नहीं की जाए तो 5 साल में ही पौधे खराब हो जाते हैं। किसान सुधीर ने बताया कि कोरोना काल में फूलों की बि ी घटकर आधी हो गई थी। उस समय वह रोजाना फूल तोड़कर खेतों में ही फैला देते थे, लेकिन समय के साथ बि ी फिर सामान्य हो गई और पहले जैसा मुनाफा होने लगा।

सीहोर के श्यामपुर में खेतों में आग से फसलें हुईं नष्ट

मिनटों में जलकर खाक हो गई तीन गांवों की दो सौ एकड़ में गेहूं की खड़ी फसल

पाटन, बरखेड़ा खरेट, तकिया में गेहूं की फसल जली

150 से 200 एकड़ रकबे में नुकसान का है अनुमान

सीहोर। जागत गांव हमार

सीहोर जिले के श्यामपुर तहसील के तीन गांवों के किसानों की गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। गांव पाटन, तकिया,बरखेडा के 100 से 200 एकड़ रकबे की फसल कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि भूसा बनाने वाली मशीन से आगजनी की घटना घटी। जिसमें लाखों रुपए की फसल जलकर खाक हो गई।

पाटन के किसान जगदीश चरकी वाले, जगदीश पिता भवर जी, राहुल पिता बद्री प्रसाद,रामसिंह पिता बंसी लाल, सुनिल पिता रामसिंह,बीरबल पिता बाबू लाल, रमेश पिता कवर जी, मांगीलाल जराती, राकेश पिता भवरजी एवं तकिया, बरखेड़ा के किसानों की भी खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। मौके पर स्थानीय किसानो द्वारा झाड़ियों के सहारे आग बुझाना चाहा लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और आगजनी का विकराल रूप में परिवर्तित हो गई थी।

- मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचती तो शायद आज पर काबू पाया जा सकता था। ट्रैक्टर से बख्खर निकाल कर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई।
- मौके पर स्थानीय लोगों ने भूसा मशीन वाले संचालक एवं ट्रैक्टर भूसा मशीन को भी कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया।
- लंबे समय से क्षेत्र के किसान फायर ब्रिगेड की मांग कर रहे हैं लेकिन गौर नहीं किया जा रहा है।
- किसान की मेहनत पल भर में स्वाहा हो गई है और उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो गया है।
- जिला मुख्यालय से यह क्षेत्र करीब 40 किमी दूर है। ऐसे में आग लगने पर दमकल को पहुंचने में काफी समय लग जाता है इस दौरान यह आग विकराल रूप धारण कर लेती है।

मौके पर समय से फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई

ऊर्जा और उर्वरक का बेहतर विकल्प गोबर,-अब पशुपालकों की इनकम हो रही डबल

भोपाल। पीएम मोदी अपने कई भाषण में गोबर को गोबरधन कह चुके हैं। उनका इशारा साफ है कि कैसे गोबर से भी धन कमाया जा सकता है। पीएम मोदी का वही प्लान अब सच होने लगा है। नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि गोबर अब ऊर्जा और उर्वरक का बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। इतना ही नहीं पीएम मोदी के ड्रीम के मुताबिक किसानों की इनकम भी डबल हो रही है। गोबर से एक नहीं कई-कई प्रोडक्ट बन रहे हैं। किसान-पशुपालकों के घर चूल्हें जलने के साथ ही गोबर से डेयरी प्लांट में ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं किसानों के खेत में मिट्टी की सेहत भी सुधर रही है। डेयरी से जुड़े एक कार्यक्रम में बोलते हुए चेयरमैन ने बताया कि एनडीडीबी ने बायो गैस से जुड़े कई मॉडल्स विकसित किए हैं। एनडीडीबी चेयरमैन डॉ. मीनेश शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान 15 राज्यों के अलग दुग्ध महासंघ और संघों के साथ कुल 25 समझौते किए गए हैं। समौते के तहत जकरियापुरा, वाराणसी और बनास प्लांट मॉडल पर काम किया जाएगा। साथ ही डेयरी सेक्टर को सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलैरिटी के लिए आगे ले जाया जाएगा। कई और नए विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत बायो गैस प्लांट की स्थापना की जाएगी। यह एक बहुआयामी पहल हैं जिसके कई लाभ होंगे। मीनेश शाह ने बताया कि केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से एनडीडीबी के नेतृत्व में गोबर को ऊर्जा और उर्वरक के एक प्रमुख संसाधन के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अच्छी खबर: अब पीडीएस में चावल की सरकार बढ़ाएगी गुणवत्ता

भोपाल। भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा प्रबंधित चावल के स्टॉक में टूटे हुए अनाज की हिस्सेदारी को मौजूदा 10 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने के उद्देश्य से एक पायलट परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का लक्ष्य राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित चावल की गुणवत्ता में सुधार करना है। यदि यह योजना सफल होती है, तो न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में लीकेज कम होगा, बल्कि इथेनॉल उत्पादन के लिए चावल की उपलब्धता भी बढ़ेगी और भंडारण लागत में कमी आएगी। पायलट योजना के तहत, एफसीआई द्वारा प्रबंधित चावल में 15 प्रतिशत टूटे हुए चावल को अलग किया जाएगा, जिसे सीधे चावल मिलों से इथेनॉल बनाने के लिए डिस्टिलरी को बेचा जाएगा। इस योजना के सफल होने पर, सरकार ने 31 अक्टूबर 2025 तक इथेनॉल उत्पादन के लिए एफसीआई से 24 लाख टन चावल आवंटित करने का लक्ष्य रखा है। भारत में चावल की आपूर्ति प्रणाली में टूटे हुए चावल का हिस्सा बहुत अधिक होता है, जो गुणवत्ता में कमी का कारण बनता है। इस योजना के तहत, एफसीआई चावल के स्टॉक से टूटे हुए चावल को अलग कर, केवल 10 प्रतिशत टूटे हुए चावल को राशन की दुकानों में वितरित करेगा। इसके परिणामस्वरूप राशन की दुकानों से मिलने वाले चावल की गुणवत्ता में सुधार होगा।

जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

1. **प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति,** राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) ईमेल-kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406
2. **प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर,** आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी आफएग्रीकल्चर, टेक्नालोजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- द्दङ्घड्ढद्दiyal.lal @shiats.edu.in, मोबा- 7052657380
3. **डा. वीरेन्द्र कुमार,** प्रोफेसर एंड हेड, पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर ढोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com मोबा- 8210231304
4. **डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक,** मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कॉके, रॉची झारखण्ड। ईमेल- ncguptabau@gmail.com, मोबा- 8789708210
5. **डा. देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश) सेवनिया, इछावर, सिहोर (मप्र) ईमेल- dpatil889@gmail.com, मोबा- 8827176184
6. **डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर,** एग्री विजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएस,विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901
7. **डा. बिनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर** आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144
8. **डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर,** परिजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार। ईमेल- drrksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793
9. **डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक,** मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड। ईमेल- deepak.swce.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836
10. **डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, विरौली, समस्तीपुर, बिहार। ईमेल-bharati.upadhya@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670
11. **रोमा वर्मा,** सब्जी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं् वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। ईमेल- romaverma35371@gmail.com, मोबा- 6267535371

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

- जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।
- समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।
- ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। **संपादकः** अजय कुमार द्विवेदी, **स्थानीय संपादकः** अरविंद मिश्रा, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)